



04 - पाखंडी बाबाओं से मुक्ति की सार्थक पहल



05 - स्वच्छ भारत के नवरो में क्यों नजर नहीं आती स्लम बस्तियां?

A Daily News Magazine

मोपाल
शनिवार, 20 जुलाई, 2024



मोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 21 अंक 313 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रु.- 2 (डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./मोपाल/4-391/2018-20)



06- पुर्नवास प्रिया में पट्टेधारियों के साथ सरकारी जमीन पर दंगवाइयों का कब्जा



07- शासकीय संगीत महाविद्यालय धार में संगीत कार्यशाला में...



subahsaverenews@gmail.com



facebook.com/subahsaverenews



www.subahsavere.news



twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

एक दिन आकाश से

गिरेंगे अंगारे

और सब कुछ भस्म

हो जाएगा

एक दिन नदी सूख जाएगी

पीने को पानी नहीं

मिलेगा

एक दिन हवा

जहरीली हो जायेगी

साँसें भी ज़हर उगलेंगी

एक दिन बाज़ार में

आदमी बिकने लगेगा

कुछ लोग खरीद लेंगे उन्हें

बहुत सस्ते में और

मौज करेंगे

एक दिन राजा का आदेश ही

कानून होगा

लोग सब उसके गुलाम होंगे ।

- दुर्गाप्रसाद झाला



प्रसंगवश

कमलेश पांडे

दुनिया के थानेदार अमेरिका ने तिब्बत के मसले पर चीन को जो दो टूक संदेश दिया है, उससे एक बार फिर वह चौखला उठा है और अमेरिकी नेतृत्व के प्रति अपनी आंखें तरेरीन शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने तिब्बत-चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देने वाले ‘रिजॉल्व तिब्बत एक्ट’ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिसमें तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दलाईलामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना शर्त सीधी बातचीत की बात कही गई है।

हालांकि, चीन ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे अस्थिरता पैदा करने वाला बताया। उसने इस बिल पर अमेरिका से साफ शब्दों में कहा कि यह चीन के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप है। कोई भी व्यक्ति या ताकत, जो चीन को नियंत्रित करने के लिए या दबाने के लिए जिजांग (तिब्बत का चीनी नाम) को अस्थिर करने का प्रयास करेगी, सफल नहीं होगी। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा व विकास हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा।

वहीं, इससे उलट निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री सिक्चोंग पेप्मा सेरिंग ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का आभार जताते हुए कहा कि यह कानून तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की बात करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में है। यह चीन के इस प्रचार व दावे को मंजूर नहीं करता कि तिब्बत कभी चीन का हिस्सा रहा है। यह धर्मगुरु दलाईलामा के आशीर्वाद से हो रहा है।

बता दें कि 1950 के दशक में चीन ने भारत की मूक सहमति से जब तिब्बत पर अपना कब्जा जमा

लिया तो वहां के सर्वोच्च धर्मगुरु यानी चौदहवें दलाईलामा 1959 में तिब्बत से भागकर भारत चले आये थे, जहां उन्होंने भारत सरकार से शरण मांगी और मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपनी निर्वासित सरकार स्थापित की। तभी से दलाईलामा से ज्यादा भारत चीन की आंखों में खटक रहा है। भारतीय प्रयासों के बाद 2002 से 2010 तक दलाई लामा के प्रतिनिधियों और चीनी सरकार के बीच नौ दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

अलबत्ता, भारत इस मुद्दे पर भले ही शांत रहा, लेकिन उसके नए मित्र अमेरिका ने उसके दर्द को समझा और एशिया में अपनी राजनीति चमकाने और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर कब्जा जमाने की गरज से चीन के विरोध के बीच रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को अमल में ला दिया। इससे पहले जम्मू-कश्मीर पर उसकी भूमिका से लगभग सभी वाकिफ हैं। इसलिए तो उसे दुनिया का थानेदार कहा जाता है। यह कटु सत्य है कि जिस काम को भारत और रूस को करना चाहिए, उसे करने का श्रेय भी अमेरिका ले चुका है।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गत 12 जुलाई 2024 को तिब्बत सम्बन्धी विधेयक रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद यह कानून बन गया है। यह प्रस्ताव तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ाने और इस हिमालयी क्षेत्र के दर्जे व शासन से सम्बन्धित विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन और तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाईलामा के बीच संवाद को बढ़ावा देने वाला है। बकौल बाइडन, मैं तिब्बतियों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए

संसद के दोनों सदनों की प्रतिबद्धता को साझा करता हूँ। मेरा प्रशासन चीन से दलाईलामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना किसी शर्त के सीधी बातचीत शुरू करने का आह्वान करता रहेगा, ताकि मतभेद दूर किये जा सकें और तिब्बत पर बातचीत के जरिए समझौता किया जा सके।

रिजॉल्व तिब्बत एक्ट में कहा गया है कि चीन की नीतियां तिब्बत के लोगों की जीवनशैली को संरक्षित करने की क्षमता को दबाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए यह कानून चीन के इस दावे को खारिज करता है कि तिब्बत प्राचीन काल से उसका हिस्सा रहा है। इस एक्ट में चीन से तिब्बत के इतिहास के बारे में गलत व भ्रामक प्रचार बन्द करने की मांग की है। यह कानून चीन के भ्रामक दावों से निपटने के लिए अमेरिका के विदेश विभाग को भी नए अधिकार देता है।

स्पष्ट है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का नहीं, बल्कि भारत का पड़ोसी रहते हुए कभी कभार उसका अभिन्न अंग भी रहा है। पहले भारत के डाक वहां जाते थे और भारतीय मुद्रा भी वहां चलती थी। जब जब भारत के शासक कमजोर हुए तो तब तब वह स्वायत्त या स्वतंत्र देश बन गया। हालांकि आजादी के बाद पंचशील के सिद्धांतों का गला घोटते हुए चीन ने साल 1959 में जिस तरह से तिब्बत को जबरन अपने भूभाग में मिला लिया और तत्कालीन भारतीय नेतृत्व ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ के गफलत में रहकर उसकी इस ओछी कार्रवाई का विरोध तक नहीं किया, वह एक अदूरदर्शी कदम साबित हुआ और उसकी कीमत आजतक भारत चुका रहा है।

अलबत्ता, अमेरिका के नए पैतरे से साफ है कि अंदरखाने में उसने भारत का विश्वास जरूर हासिल

किया होगा। क्योंकि चीन जिस तरह से भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकते हुए उसे दक्षिणी तिब्बत का भूभाग करार देता है, उसके परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी कानून ने यह साफ कर दिया है कि जब तिब्बत ही चीन का हिस्सा नहीं है तो फिर भारतीय भूभाग पर उसका दावा वाकई फर्जी है।

वहीं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीनी हरकतें भी स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। नेपाल से लेकर भूटान की सीमा तक जो उसकी हरकतें हैं, उसके मद्देनजर रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को चीनी चालों पर एक करारा तमाचा भी समझा जा सकता है, जो भारत ने अपने नए और रणनीतिक दोस्त से दिलवाई है। अब भी यदि चीन नहीं चेतेगा तो तिब्बत का उसके हाथ से फिसलना तय है।

अमेरिका ने जिस तरह से रूस को यूक्रेन में उलझाया, उसी तरह से अब वह चीन को तिब्बत में उलझायेगा। क्योंकि ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने से अच्छा है तिब्बत पर घेरेना, ताकि दो मोर्चे पर एक साथ उलझने की गलती वह कर बैठे। अब भारत को भी चाहिए कि चीनी विश्वासघात का बदला ले और तिब्बत मुक्ति संग्राम को शह प्रदान करके अपनी ऐतिहासिक भूल को सुधारे। स्पष्ट है कि रिजॉल्व तिब्बत एक्ट चीन के लिए एक खतरनाक पैगाम लेकर आया है। इसके कूटनीतिक मायने इस बात की चुगली कर रहे हैं कि पर्ल/रिंग पॉलिसी के माध्यम से भारत को घेरते रहने की अनवरत चाल चलते रहने वाला चीन अब खुद ही तिब्बत के मसले पर अमेरिकी जाल में फंसकर तड़फड़ने वाला है।

(प्रभासाक्षीफ डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन से दुनियाभर में मची अफरा-तफरी

- भारत समेत एयरलाइन कंपनियों का कामकाज टप, चेक-इन भी प्रभावित
- दुनियाभर में 1 हजार प्लाइट कैंसिल
- बैंक, स्टॉक मार्केट और टीवी चैनल पर भी असर



नई दिल्ली (एजेंसी)। एंटीवायरस 'क्राइस्ट्राइक' के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में शुक्रवार को दिक्कत आ गई। इसकी वजह से दुनियाभर में एयरलाइंस, टीवी टेलिक्रास्ट, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे कई देशों में 1 हजार से ज्यादा प्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। वहीं 3 हजार विमानों ने देरी से उड़ान भरी। भारत में, 5 एयरलाइन- इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक-इन और प्लाइट अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से प्रभावित हुई है।



● क्राउडस्ट्राइक के अपडेट के कारण माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस टप हुई

दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ यूजर्स को अपने लैपटॉप पर नीली स्क्रीन दिखाई दे रही है। इससे उनके सिस्टम ऑटोमैटिकली रीस्टार्ट या शटडाउन हो गए हैं। डेल टेक्नोलॉजीज ने कहा कि यह समस्या हालिया क्राउडस्ट्राइक अपडेट के कारण हुई है। क्राउडस्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिब्योरिटी सॉल्यूशन देता है। क्राउडस्ट्राइक के अपडेट के कारण ही माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है।

स्पाइसेज ने कहा तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे

स्पाइसेज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, वर्तमान में हम अपने सेवा प्रदाता के साथ तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग का प्रबंधन सहित ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। परिणामस्वरूप, हमने सभी हवाई अड्डों पर मैनुअल चेक-इन और



बोर्डिंग प्रक्रियाओं को सक्रिय कर दिया है। हम आगामी यात्रा योजना वाले यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे काउंटरों पर चेक-इन पूरा करने के लिए सामान्य से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें। हम इसके कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करते हैं और आपको आश्चस्त करते हैं कि हमारी टीमें इन मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए हमारे सेवा प्रदाता के साथ लगन से काम कर रही हैं।

उ.प्र. में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे

- गोरखपुर में एनडीआरएफ तैनात, मुंबई में 10 घंटे में 101मिमी बारिश; 13 राज्यों में अलर्ट,
- पोरबंदर में भारी बारिश के बाद बाढ़
- सुपौल में महादेव का मंदिर भी कोसी नदी में समाया

नई दिल्ली/लखनऊ/पटना (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग 1 हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर में है। यहां राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की टीम 100 नावें लगाकर राहत-बचाव के काम में जुटी है।

गंगा नदी भी उफान पर गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा में 30 घाट डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट के गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। अस्सी घाट की पुराने आरती स्थल की जगह बदल दी गई है। आज आरती 4 फीट पीछे होगी।



कर्नाटक में दीवार गिरने से तीन की मौत

उधर कर्नाटक में शुक्रवार सुबह भारी बारिश हुई। शिगांव के मदापुरा गांव में एक घर की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 2 बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा, 39 की मौत

प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां फूँकी, सरकारी चैनल में आग लगाई; 300 लोग भारत पहुंचे

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हफ्ते भर से जारी विरोध-प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार शाम बांग्लादेश के मुख्य सरकारी टीवी चैनल बीटीवी के मुख्यालय में आग लगा दी। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों प्रदर्शनकारी बीटीवी ऑफिस के कैमरे में घुस आए और 60 से ज्यादा गाड़ियां फूँक दीं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल ही बीटीवी को इंटरव्यू दिया था। छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुईं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में 18 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 2500 से अधिक लोग घायल हुए। बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कम से कम 39 लोगों की मौत हुई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोक के निर्माण की समीक्षा

श्री रामराजा लोक ओरछा में भगवान श्रीराम के प्रसंगों को दर्शाया जाए : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ओरछा में विकसित हो रहे श्री रामराजा लोक में भगवान श्रीराम के वनवास अवधि में वर्तमान मध्यप्रदेश के भू-भाग में बिताई गई समयावधि में हुए प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक लोकों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन स्थानों पर लाइट एंड साउंड शो की प्रस्तुति की व्यवस्था भी हो। प्रदेश में विकसित हो रहे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक लोक के आय के साधन सुनिश्चित करते हुए उनके निर्माण और प्रबंधन प्रक्रिया तय की जाए, ताकि सभी लोकों का संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो सके। लोकों का बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित विभागों जैसे संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की स्थानीय स्तर पर संचालन समिति बनाई जाए। बैठक में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव संस्कृति तथा पर्यटन श्री शिवशेखर सुकुला तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।



भादवा माता लोक से आयुर्वेदिक अस्पताल को जोड़ा जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुनिश्चित करने को कहा कि विकसित हो रहे सभी धार्मिक और सांस्कृतिक लोकों के निर्माण कार्य में आकरष्यन इस प्रकार से हो कि सौंदर्यीकरण और आकर्षण दीर्घकालीन बना रहे। उन्होंने संत रविदास लोक, सागर में शोधपीठ और शैक्षणिक संस्था विकसित करने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने कहा कि भादवा माता लोक नीमच में श्रद्धालु दर्शन के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी आते हैं। भादवा माता लोक से आयुर्वेदिक अस्पताल और फिजियोथेरेपी सेंटर को भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंदिर जिस स्थापत्य शैली में बने हैं, उनकी विशेषताओं का संरचनाओं के निर्माण में अनुसरण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश की कला-संस्कृति-स्थापत्य और प्रमुख व्यंजनों पर केंद्रित मेले देश के अन्य राज्यों में आयोजित किए जाएं, इससे प्रदेश के पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

संसद के बजट सत्र से पहले रणनीति बनाने में जुटा एनडीए, विपक्षी दलों को एक सुर में देगा जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद का आगामी बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इसके 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा संसद सत्र है और इसलिए केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और केंद्र सरकार कई स्तरों पर इसे लेकर तैयारी कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने पिछले सत्र के दौरान, जिस अंदाज में सरकार को घेरने की कोशिश की थी और जिस तरह से विपक्ष के कई राजनीतिक दल राहुल गांधी का साथ देते नजर आए। सरकार ने तैयार की काउंटर रणनीति- पिछले सत्र में विपक्ष के रवैये को देखते हुए भाजपा और सरकार ने सोमवार से शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर काउंटर रणनीति तैयार कर ली है।

सीएम हिमंता बोले-

2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा असम

दिसपुर (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिरसा सरमा ने शुक्रवार (19 जुलाई) को कहा राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30 प्रतिशत बढ़ रही है। ऐसे में साल 2041 तक



असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। यह हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एंबेसडर बन जाते हैं तब इस पर नियंत्रण लग सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। असम सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेमोग्राफिक डेटा के मुताबिक असम की मुस्लिम आबादी 40 फीसदी हो गई है। जबकि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में करीब 16 फीसदी ही बढ़ रही है।

छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2 आईडी ब्लास्ट...2 जवान शहीद, 6 घायल

बीजापुर/दंतेवाड़ा (एजेंसी)। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर पिछले 24 घंटे में 2 अलग-अलग जगह आईडी ब्लास्ट हुए। जिसकी व्पोट में आने से



2 जवान शहीद हो गए, वहीं 6 जवान घायल हैं। घायलों में 2 डीआरजी के जवान हैं, बाकी एसटीएफ के हैं। इधर, दंतेवाड़ा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में जवानों ने 1 महिला माओवादी को मार गिराया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इन तीनों जिलों के बॉर्डर पर नक्सलियों के दरभ्रा डिवीजन, पश्चिम वस्तर डिवीजन और मिलिट्री नंबर 2 के नक्सली मौजूद हैं।

चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी

यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, 8 तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च ब्रिज पर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। संगलदान से रियासी के बीच चलने वाली यह ट्रेन सर्विस उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

इस ब्रिज पर 20 जून को ट्रेन का ट्रायल रन हुआ था। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। यह ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। एफिल टॉवर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किमी लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है।

यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिकटर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को झेल सकता है। पाकिस्तानी सीमा से इसका एरियल डिस्टेंस महज 65 किमी है। इस ब्रिज के शुरू होने से कश्मीर घाटी हर मौसम में ट्रेन के जरिए भारत के दूसरे हिस्सों से जुड़ जाएगी। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट 1997 से शुरू हुआ था। इसके तहत 272 किमी की रेल लाइन बिछाई जानी थी। अब तक अलग-अलग फेज में 209 किमी लाइन बिछाई जा चुकी है। इस साल के अंत तक रियासी को कटरा से जोड़ने वाली आखिरी 17 किमी लाइन बिछाई जाएगी, जिसके बाद जम्मू के रियासी से कश्मीर के बारामूला तक पैसेंजर ट्रेवल कर सकेगा।



20 साल में बनकर तैयार हुआ ब्रिज

आजादी के 76 साल पूरे होने के बाद भी कश्मीर घाटी बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी। 22 फरवरी 2024 तक कश्मीर घाटी तक सिर्फ नेशनल हाईवे- 44 के जरिए जाया जा सकता था। बर्फबारी होने पर कश्मीर घाटी जाने वाला ये रास्ता भी बंद हो जाता था। इसके अलावा कश्मीर जाने के लिए जम्मू-तवी तक ही ट्रेन जाती थी, जहां से करीब 350 किलोमीटर लोगों को सड़क मार्ग से जाना पड़ता था। जवाहर टनल होते हुए गुजरने वाले इस रास्ते से लोगों को जम्मू-तवी से घाटी जाने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था। 2003 में भारत सरकार ने सभी मौसम में कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला लिया।

भारत स्वतंत्र हो गया, स्वाधीनता के लिए जारी है आंदोलन : यशवंत इंदापुरकर

हमें अकबर की वंशावली तो पढ़ाई, राम की नहीं, इस नैरेटिव के खिलाफ हमारी लड़ाई : अशोक श्रीवास्तव

भोपाल। भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन उसे स्वाधीनता में बदलने का आंदोलन अभी चल रहा है। अंग्रेजों ने कुटिलतापूर्वक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया और भारत को मानसिक गुलाम बना दिया। इससे उबरने का एक ही तरीका है- जनजागरण। यही कार्य देवर्षि नारद करते थे। यह बात विश्व संवाद केंद्र की ओर से आयोजित देवर्षि नारद जयंती समारोह एवं परिचर्चा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य यशवंत इंदापुरकर ने कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दूरदर्शन के वरिष्ठ संपादक अशोक श्रीवास्तव उपस्थित थे। अध्यक्षता विश्व संवाद केंद्र न्यास के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र माहेश्वरी ने की। यह कार्यक्रम नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन के ‘समागम केंद्र’ में आयोजित हुआ। जिसमें भोपाल महानगर के पत्रकार, बुद्धिजीवी, मातृशक्ति, कला एवं सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए।

‘सांस्कृतिक पुनर्जागरण और मीडिया की भूमिका’ विषय पर श्री इंदापुरकर ने कहा कि डॉ. हेडोवार जी ने 1911 में कहा था कि समाज में जागरूकता और प्रशिक्षण बेहद आवश्यक है। यह बात विख्यात कम्युनिस्ट नेता एमएन राय ने भी कही। सभी मनीषियों का मानना है कि जब तक संपूर्ण समाज नहीं बदलेगा, तब तक भारत के पुनर्र्थान का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद का नाम कलह कराने वाले के रूप में ही प्रचारित किया जाता रहा है। लेकिन उस विचार को बदलने का काम हम सबने किया है। कुछ वर्ष पहले जब मीडिया के साधियों के बीच हम देवर्षि नारद जयंती

मनाने के कार्यक्रम को लेकर जाते थे तो उपहास हुआ करता था। लेकिन वह धारणा बदली है और आज अधिकांश प्रतिष्ठित पत्रकारों की टेबल पर देवर्षि नारद की तस्वीर मिलती है, क्योंकि अब पत्रकारों ने अपने आद्य पुरुष को



पहचान लिया है। उन्होंने मान लिया है कि देवर्षि नारद विश्व के कल्याण के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। जब हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं तो हमें अपने आसपास घटित होने वाली सकारात्मक चीजों को भी देखना होगा। भारत के सांस्कृतिक उत्थान में मीडिया की बहुत प्रभावी भूमिका है। इस दायित्व को मीडिया के बंधुओं को पहचानना चाहिए।

इस अवसर पर प्रख्यात पत्रकार एवं डीडी न्यूज नई दिल्ली के संपादक अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि हमें बचपन से पाठ्यक्रम में अकबर की वंशावली पढ़ाई गई लेकिन राम की नहीं। यह सब योजना पूर्वक किया गया। हमें किताबों में यह तो पढ़ाया गया कि अकबर महान थे। बाबर महान थे। प्राइमरी से हमें अकबर की वंशावली पढ़ाई गई, लेकिन राम की वंशावली नहीं पढ़ाई गई। इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को खत्म किया गया। हमारी लड़ाई इसी नैरेटिव

के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मास मीडिया और बॉलीवुड ने देवर्षि नारद जी की तस्वीर चुगलखोर की बना दी थी। यह स्थिति आजादी के बाद से लगातार बनी है, क्योंकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया और हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कहानी कही जाती रही। फिल्मों ने इसे मजबूत किया। फिल्मों में भारतीय संस्कृति के प्रतीकों को लंबे समय तक गलत ढंग से दिखाया। उसके कारण भारतीय संस्कृति के प्रति एक भ्रामक छवि युवाओं के मन में बन गई। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को पुनर्जागरण का सबसे बड़ा प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आज पाठकों एवं दर्शकों के दबाव के कारण मीडिया रामलला का अखंड कवरेज दिखाता है। यह मीडिया का प्रायश्चित है, क्योंकि एक समय में मीडिया के एक हिस्से ने विवादित ढांचा गिराते समय कारसेवकों की छवि को सांप्रदायिक बताया था। यहां तक कि रामजन्म भूमि पर विवादित ढांचे को गिराने के बाद शौचालय बनाने की बात भी की गई थी। आज मीडिया ने अपना दृष्टिकोण बदला है क्योंकि समाज में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता आयी है।

कार्यक्रम की प्रस्तावना केंद्र के न्यासी भावेश श्रीवास्तव ने रखी। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र माहेश्वरी ने आभार ज्ञापन और संचालन वरिष्ठ पत्रकार डॉ. सुदीप शुक्ल ने किया। इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर, शिवजी नगर की छात्राओं ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी।

हरित संरक्षकों का होगा सम्मान

भोपाल। राजधानी के कुछ संगठनों ने मिलकर समाज सेवा की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए नया आयाम स्थापित किया है। गौरतलब है कि 20 जुलाई 2015 को अमेरिका के कैलीफोर्निया में सेनडियेगो शहर के महापौर ने म09प्र0 के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री मनीष शंकर शर्मा के उत्कृष्ट सामाजिक योगदान और भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ करने पर मनीष शंकर शर्मा को उल्लेख किया था जो कि पहली बार किसी भारतीय के नाम से अमेरिका में हुआ था। तभी से राजधानी में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस पर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इसी कड़ी में और मध्यप्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले राज्य के गौरव श्री शर्मा से प्रेरणा लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था लार्यंस क्लब, कैरियर समूह, आदि संगठनों ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार (संभवतः भारत के इतिहास में भी) उन महानुभावों का सम्मान करने का निर्णय लिया है जो वाकई हमारे वृक्षों , पौधों और बागवानों का -24 घंटे, सातों दिन ,वर्ष भर - निरंतर संरक्षक करते हैं। हरित संरक्षक (माली बंधु) साथ ही में उन सुस्था संवर्धकों का भी सम्मान किया जायेगा जो इन बागवानों को सुरक्षित रखते हैं।

गांव में एक भी हेल्थ सेंटर मानक नहीं, सरकार से जवाब तलब

भोपाल। मध्यप्रदेश में बदहाल ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हार्डकोट इंदौर ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। गांधीवादी विचारक एवं लेखक चिन्मय मिश्र ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी। इसपर आज उच्च न्यायालय की युगल पीठ, जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी तथा जस्टिस दुयुष्म वेंटक रमन्ना ने नोटिस जारी कर मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता चिन्मय मिश्र की ओर से अधिवक्ता अभिनव धनोङ्कर द्वारा पैरवी की गई थी।

याचिका के पक्ष में तर्क दिया गया कि स्वास्थ्य का अधिकार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ तथा पूर्ण उपलब्धता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार की श्रेणी में आता है। यह एक मौलिक अधिकार है तथा सरकार का यह दायित्व है कि ग्रामीण इलाकों में व्याप्त बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार करे।

याचिका का आधार यह है कि मध्यप्रदेश के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार मध्यप्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की नींव माना जाने वाला एक भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राथमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर भारत शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार कार्यरत नहीं हैं। इन

सेंटर्स में न तो उपयुक्त सुविधाएं हैं और न ही डॉक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हैं।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। शिशु मृत्यु दर जहां सम्पूर्ण भारत में 32 प्रति 1000 है वहीं मध्य प्रदेश में यह 48 है। माताओं में मृत्यु दर सम्पूर्ण देश में 113 है वहीं मध्यप्रदेश में 173 है। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में केवल 55 फीसदी महिलाओं की ही प्रसव के दौरान 4 बार देखरेख हो पाती है। जहां तक गर्भावस्था के समय में आयरन फोलिक एसिड हर गर्भवती महिला के लिए आवश्यक होता है लेकिन यह केवल 10 फीसदी गर्भवती महिलाओं को ही मिल पाता है। ग्रामीण प्रदेश की 70 फीसदी महिलाएं इससे वंचित रहती हैं, जिसका विपरीत प्रभाव उनपर तथा उनके होने वालों बच्चों पर पड़ता है। केवल 42 फीसदी महिलाओं द्वारा ही प्रसव के 1 घंटे के भीतर नवजात जो स्तनपान करवाया जाता है। मध्य प्रदेश में 58 फीसदी से अधिक महिलाएं खून की कमी से प्रभावित हैं।

2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार मध्य प्रदेश में 309 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, जिसमें हर एक सेंटर में एक फिजिशियन, एक सर्जन, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा एक बच्चों के चिकित्सक की नियुक्ति होना आवश्यक है, परन्तु 309 में से

एक भी ऐसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, जहां इस सब की नियुक्ति हो। कुल मिलाकर 324 सर्जन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और 302 पद खाली हैं। 324 जनरल फिजिशियन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और बाकी 302 पद खाली हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ में 324 में से केवल 21 पद भरे हैं बाकी 303 पद खाली हैं। बच्चों के विशेषज्ञों हेतु आवश्यकता 309 नियुक्तियों की है, परन्तु केवल 60 पद ही स्वीकृत हैं, जिनमें से भी केवल 11 पर ही नियुक्तियां हुई हैं। सबसे चौकाने वाले स्थिति यह है कि, मध्य प्रदेश में एक भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है और केवल 5 ही एनेस्थेसिस्ट नियुक्त हैं।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार मध्य प्रदेश में 28 फीसदी सब सेंटर्स की कमी है, 47 फीसदी प्राथमरी हेल्थ सेंटर तथा 45 फीसदी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की कमी है। रिपोर्ट के अनुसार जितने भी सेंटर हैं, उनमें से एक भी सेंटर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यरत नहीं है। हर सेंटर में कोई ना कोई कमी है जिसके कारण मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति है, और इसका विपरीत प्रभाव सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है।

एक भी ऐसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, जहां इस सब की नियुक्ति हो। कुल मिलाकर 324 सर्जन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और 302 पद खाली हैं। 324 जनरल फिजिशियन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और बाकी 302 पद खाली हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ में 324 में से केवल 21 पद भरे हैं बाकी 303 पद खाली हैं। बच्चों के विशेषज्ञों हेतु आवश्यकता 309 नियुक्तियों की है, परन्तु केवल 60 पद ही स्वीकृत हैं, जिनमें से भी केवल 11 पर ही नियुक्तियां हुई हैं। सबसे चौकाने वाले स्थिति यह है कि, मध्य प्रदेश में एक भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है और केवल 5 ही एनेस्थेसिस्ट नियुक्त हैं।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार मध्य प्रदेश में 28 फीसदी सब सेंटर्स की कमी है, 47 फीसदी प्राथमरी हेल्थ सेंटर तथा 45 फीसदी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की कमी है। रिपोर्ट के अनुसार जितने भी सेंटर हैं, उनमें से एक भी सेंटर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यरत नहीं है। हर सेंटर में कोई ना कोई कमी है जिसके कारण मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति है, और इसका विपरीत प्रभाव सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है।

एनसीबी ने मुंबई में 10 करोड़ कीमत के मेफेड्रोन ड्रस के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 10 करोड़ की कीमत वाले 5 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रस के साथ एम एस शेख नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि बारे में गुप्त सूचना मिली थी। आरोपी ने मुंबई में ड्रस सप्लाई करने के लिए हैदराबाद से मंगवाया था। शेख मेफेड्रोन की इंटर स्टेट तस्करी गैंग में शामिल है।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एनजीओ कॉमन कोज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटररेस्ट लिटिगेशन ने बॉन्ड के लेनदेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। इस पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी।

गुजरात में वलसाड और सूरत स्टेशन के बीच मालगाड़ी पटरी से उतरी, रेल सेवाएं प्रभावित

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात में वलसाड और सूरत स्टेशनों के बीच शुक्रवार को एक मालगाड़ी की डिब्बा पटरी से उतर गया। हालांकि इस दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पश्चिमी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे डुंगरी स्टेशन के पास हुई इस घटना के कारण मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। मालगाड़ी सूरत की तरफ जा रही थी।

78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम होगी- विकसित भारत



नईदिल्ली (एजेंसी)। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए थीम विकसित भारत रखी गई है। जो 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के मुताबिक है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए. भारत भूषण बाबू ने एक्स पर एक पोस्ट में यह घोषणा की, जिसमें उन्होंने लाल किला और विकसित भारत के नारे के साथ एक पोस्टर भी शेयर किया है। 2047 में भारत अपनी आजादी का 100वां साल मनाएगा।

एनसीबी ने मुंबई में 10 करोड़ कीमत के मेफेड्रोन ड्रस के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 10 करोड़ की कीमत वाले 5 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रस के साथ एम एस शेख नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि बारे में गुप्त सूचना मिली थी। आरोपी ने मुंबई में ड्रस सप्लाई करने के लिए हैदराबाद से मंगवाया था। शेख मेफेड्रोन की इंटर स्टेट तस्करी गैंग में शामिल है।

कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश

‘हर दुकान पर नेम प्लेट लगाएं दुकानदार’

● प्रियंका गांधी ने कहा-यह लोकतंत्र पर हमला; मुस्लिम जमात फैसले के समर्थन में

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने यह आदेश दिया। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। इसके अलावा, हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया। कहा- यह फैसला



चुनावी लाभ के लिए है।

एडीजी बोले- यह नया आदेश नहीं-मेरठ जोन एडीजी डीके ठाकुर ने कहा- यह कोई नया आदेश नहीं है। इसका पिछले साल भी पालन कराया गया था। आदेश को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है। जाति-धर्म के नाम पर विभाजन का समर्थन नहीं- चिराग पासवान-केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

ने कहा कि वह जाति या धर्म के नाम पर किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी गाइडलाइंस का विरोध करते हुए कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।

भोपाल पहुंचे तीर्थ यात्रियों का स्वागत

हर-हर गंगे के नारों से गुंजायमान हुआ रेलवे स्टेशन
भोपाल। विश्व शांति की कामना लेकर 300 से अधिक तीर्थ यात्रियों का जत्था गंगा की आरती और गुरु पूजन करने मुंबई से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। गुरुवार को तीर्थ यात्रियों की ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व जागृत हिंदू मंच के संरक्षक डॉ. दुर्गेश केसवानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जत्थे का जोरदार स्वागत किया।



भोपाल स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों की ट्रेन पहुंचते ही चारों ओर हर-हर गंगे के नारे गुंजने लगे। इस तरह के स्वागत से तीर्थ यात्री भाव-विभोर हो उठे। इस दौरान मंत्री शिवाजी पटेल ने कहा कि पूरे विश्व में मां गंगा के प्रति अद्भुत समर्पण है। उन्होंने तीर्थ यात्रियों का स्वागत कर अपनी शुभकामनाएं दीं। साथ ही कहा कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। भाजपा प्रवक्ता डॉ दुर्गेश केसवानी ने श्रद्धालुओं को शुभकामना देते हुए उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की है। एडवोकेट सुनील जैन ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दीं, और कहा कि मां गंगा हर किसी के जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि लाएं।

हरिद्वार जाने वाले जत्थे में उल्हासनगर के पूर्व उप महापौर विनोद तालेरजा, जगदीश तेजवानी, डॉ जैसवानी के नेतृत्व में 400 लोगों का जत्था हरिद्वार जा रहा है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर जत्थे का स्वागत स्वस्तिवाचन कर हर फूल माला पहनाकर और भगवान श्री राम जी, झूलेलाल जी, गंगा मैया जी के नारे लगाकर किया गया। इस अवसर पर मंच के पदाधिकारी अनिल मोहनानी, शिव इसरानी, यश कुमार, श्रेयांश जैन, मनोज राय चंदानी बजरांग दल के विवेक कुंटे, पंडित विपिन दुबे, कान्हा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डॉ. दुर्गेश केसवानी ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना

भोपाल। राजधानी भोपाल के अशोक गार्डन थाने में सुंदरकांड पाठ को लेकर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। जिसको लेकर कांग्रेस थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन दे रही है। इसी बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश केसवानी ने निशाना साधा है कि दिग्विजय सिंह एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं और उन्हें खुश करने के लिए हमेशा हिंदू धर्म पर आरोप लगाते आए हैं। दिग्विजय सिंह अगर सुंदरकांड पढ़ते होते तो वह कभी राम मंदिर पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाते। दिग्विजय सिंह अगर सुंदरकांड पढ़ते होते तो भोपाल की जनता उन्हें 3.50 लाख वोटों से नहीं हराती। अगर दिग्विजय सिंह सुंदरकांड पढ़ते होते तो उन्हें राजगढ़ की जनता नहीं हराती। दिग्विजय सिंह केवल विशेष वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए हिंदू पक्ष पर हमलावर रवैया अपनाते हैं।

आज से तीसरे दौर में शुरू होगी वर्षा

पुष्य नक्षत्र पर वर्षा सवार
पंडित विनोद गौतम, भोपाल। आज शनिवार 20 जुलाई को सूर्य 10:51 दिन से पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगे, जिससे वर्षा का तीसरा दौर शुरू होगा, वर्षा के आठ नक्षत्रों में यह तीसरा नक्षत्र है जो आगामी 15 दिनों तक बारिश कराएगा इस नक्षत्र के योग संज्ञा करक नक्षत्र स्त्री, पुरुष है, चंद्र नक्षत्र - चंद्र, सूर्य एवं इस नक्षत्र में वर्षा का वाहन मंडूक है यह श्रेष्ठ वर्षा के संकेत देता है कई क्षेत्रों में अति वर्षा से हानि की स्थिति बन सकती है। विचित्र तेज बारिश के लिए यह श्रेष्ठ नक्षत्र संपूर्ण जगह बारिश कराएगा, वायुवेग के साथ बिजली गिरने की घटनाएं अधिक होगी। वर्तमान आकाशीय गोचरीय ग्रह स्थिति के अनुसार पुरु, मंगल की युति एवं सूर्य के साथ त्रिग्रही योग उत्तम वर्षा कारक है।

भोपाल में प्रॉपर्टी डीलर पर धोखाधड़ी की एफआईआर कटारा हिल्स में प्लॉट बेचने के नाम पर लोगों से की 43 लाख रुपए की ठगी

भोपाल (नप्र)। कटारा हिल्स पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। आरोपी ने करीब आधा दर्जन लोगों से 43 लाख रुपए ठगे हैं। रकम लेने के बाद जालसाज ने एक भी ग्राहक को प्लॉट नहीं दिया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ शिकायती आवेदन ठगी का शिकार लोगों ने दिया। जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को तलाश शुरू कर दी है।

न रजिस्ट्री की, न रुपए लौटा रहा था

सब इंस्पेक्टर सविता वासुदेव के मुताबिक संजय सिंह समेत करीब आधा दर्जन लोगों ने पुलिस को लिखित में आवेदन दिया था कि उन्होंने महेश मीणा से उसकी कॉलोनी में प्लॉट खरीदा था। उसके बाद से वह उसकी रजिस्ट्री भी नहीं करा रहा है और ना ही रकम वापस लौटा रहा है। पुलिस ने जब महेश मीणा से पृच्छाछ की तो उसने बताया कि उसने नारायण पाटीदार से जमीन 9 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदी थी, लेकिन तय समय में जमीन के पैसे अदा नहीं कर सका। इसलिए उसका अनुबंध खत्म हो गया, और उसी जमीन को लेकर मैंने लोगों से रुपए लिए थे। मामले को खुलासा होने पर महेश से पुलिस ने कहा कि खरीददारों की रकम वापस लौटा दे, लेकिन उसने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी महेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अब पुलिस उसे जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

बेहतर प्लानिंग और आधुनिक टेक्नोलॉजी से संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है सुनिश्चित : उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

‘अर्बन मोबिलिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी’ सेमिनार का शुभारंभ किया

भोपाल (नप्र)। उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि बेहतर प्लानिंग और आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से सुनियोजित, संवहनीय विकास होता है साथ ही संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। देश को सुनियोजित रूप से आगे बढ़ने में सभी वर्गों के प्रबुद्धजनों का योगदान अहम है। हम सब मिलकर भारत को विश्व-गुरु बनायेंगे। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने भोपाल के होटल ताज में कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) द्वारा अर्बन मोबिलिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विषय पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ किया।

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अधोसंरचनात्मक विकास के साथ कृषि और औद्योगिक क्रांति से नागरिकों की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में निरंतर



विस्तार हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण को केंद्रित रख कर योजनाबद्ध रूप से विकास किया जा रहा है ताकि आगामी पीढ़ियाँ संरक्षित रहें। उप-मुख्यमंत्री ने सीईएआई द्वारा शहरों के सुनियोजित विकास के

संदर्भ में आयोजित सेमिनार की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस सेमिनार से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आयेंगे जिनका उपयोग सरकार द्वारा दूरगामी विकास की योजना में किया जायेगा।

कांग्रेस की कमजोरी तलाशने शुरू होंगी संभागीय बैठकें

22 जुलाई को भोपाल संभाग के जिला, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे पटवारी



भोपाल (नप्र)। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब संगठन में कमजोरी की वजह तलाशने के लिए संभागीय बैठकें शुरू करने जा रही है। इन बैठकों में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाकर चर्चा की जाएगी। इसकी शुरुआत 21 जुलाई से हो रही है।

पटवारी पूछेंगे कमजोरी के कारण, मजबूती के ऑप्शन भी जानेंगे

पीसीसी में दो दिनों तक होने वाली बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी 22 जुलाई को भोपाल संभाग और 23 जुलाई को नर्मदापुरम संभाग के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ चर्चा कर कांग्रेस की कमजोरी के स्थानीय कारण पूछेंगे। ब्लॉक अध्यक्षों से पटवारी यह जानने की कोशिश भी करेंगे कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है।

भोपाल के कई इलाकों में बारिश | बड़ा तालाब में 1660.70 फीट पहुंचा लेवल

भोपाल (नप्र)। भोपाल में शुक्रवार को दोपहर बाद कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। कई जगह बूंदबांदी हुई है। मौसम विभाग ने आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर, 24 घंटे के दौरान तेज बारिश होने से भोपाल की लाइफ लाइन बड़ा तालाब में पानी का लेवल बढ़ गया है। शुक्रवार सुबह तालाब में लेवल 1660.70 फीट पहुंच गया। एक दिन में ही कोलार डैम में डेढ़ और केरवा डैम में ढाई फीट पानी बढ़ा है। कलियासोत डैम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में

आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। पिछले 24 घंटे में डेढ़ इंच बारिश हुई।

करोड़ों खर्च,मेयर-कमिश्नर के दावे फेल, पानी-पानी हुई राजधानी,जलभराव- भोपाल में सीवेज सिस्टम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी थोड़ी तेज बारिश होते ही राजधानी पानी-पानी हो जाती है। ऐसा ही गुरुवार -शुक्रवार को हुई तेज बारिश के दौरान भी हुआ। एक घंटे की तेज बारिश में पूरी राजधानी तरबतर हो गई।

मोहन सरकार की ढाल कैलाश विजयवर्गीय : राकेश शर्मा

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय डॉ. मोहन यादव की सरकार में लगातार मीडिया में सरकार का पक्ष पूर्ण शिद्द और सटीकता से रखते हैं। जब-जब मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की ब्रीफिंग का काम कैलाश विजयवर्गीय करते हैं। कई ऐसे विषय जिसका जवाब सरकार में किसी के पास नहीं रहता, ऐसे कठिन विषय पर भी मीडिया का सामना कैलाश विजयवर्गीय एक चञ्चल की तरह करते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस बार विपक्ष लगातार हमलावर रह, नर्सिंग से जुड़ा हुआ विषय सड़क से सदन तक छाया रहा, विधानसभा में विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, तब सरकार का पक्ष पूरी दमदारी से कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में रखा। पूरे समय एक ढाल की तरह विधानसभा में सरकार की रक्षा कैलाश विजयवर्गीय ने की और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिये।

सदन के वरिष्ठ नेता के साथ-साथ लंबा राजनीतिक अनुभव कैलाश विजयवर्गीय के साथ जुड़ा हुआ है। हर दल का विधायक कैलाश विजयवर्गीय का सम्मान करता है और उनके राजनीतिक अनुभव का कायल है। ऐसे गुरुण कम ही राजनीतिक व्यक्तियों में दिखाई देते हैं। मीडिया बंधुओ से भी कैलाश विजयवर्गीय के बड़े आत्मीय संबंध हैं जिसका लाभ मोहन सरकार को मिलता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला छिंदवाड़ा को माना जाता था। कांग्रेस के छिंदवाड़ा किले को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का अभेद्य दुर्ग माना जाता था जिसे



भेदने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लंबे समय से कर रहा था। तब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की जवाबदारी अपने सबसे मजबूत सेनापति कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी। पार्टी संगठन द्वारा सौंपी गई जवाबदारी पर कैलाश विजयवर्गीय 100 प्रतिशत खरे उतरे और कांग्रेस का छिंदवाड़ा का किला चुनाव में ढहा दिया।

लोकसभा की हार के बाद कमलनाथ संभल नहीं पाए, अभी अमरवाड़ा में हुए विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। कैलाश विजयवर्गीय की बिछाई हुई बिसात का असर अभी तक छिंदवाड़ा में है। जब-जब सरकार और संगठन को कैलाश विजयवर्गीय की

आवश्यकता पड़ती है वह पूर्ण समर्पण के साथ सरकार और संगठन के साथ खड़े रहते हैं। नए कार्यकर्ताओं को कैलाश विजयवर्गीय से प्रेरणा लेना चाहिए कि अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ संगठन और सरकार की सेवा किस तरह की जाती है। यह कई बार सिद्ध हुआ है कि जब तक कैलाश विजयवर्गीय जैसा मजबूत स्तंभ डॉ मोहन सरकार के साथ जुड़ा हुआ है तब तक सरकार पर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आ पाएगा।

कैलाश विजयवर्गीय जैसे संपूर्ण नेता पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और हर कार्यकर्ताओं को गर्व है। राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किये गए कार्य मौल के पथर साबित हो रहे हैं। अभी इंदौर में पौधरोपण में कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में इंदौर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। आज पौधरोपण को लेकर पूरे देश में इंदौर की चर्चा हो रही है जिसका पूरा श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए अवकाश 'एक पौधा मां के नाम' को धरातल पर उतरने का काम कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। पौधरोपण के महा अभियान से जुड़कर कैलाश विजयवर्गीय ने जो काम किया है उसे आने वाली पीढ़ी वर्षों तक याद रखेगी। इस अभियान से कैलाश विजयवर्गीय इतनी शिद्दत से जुड़े कि उन्होंने अपने खाने-पीने और आराम की चिंता नहीं की। इंदौर में ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण हो, उसमें जुटे रहे जिसका परिणाम आज पौधरोपण में इंदौर का जिक्र पूरे देश में किया जा रहा है।

सेमिनार में सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा, सीईएआई के प्रेसिडेंट श्री आरएस शर्मा सहित सीईएआई के पदाधिकारी, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और छात्र उपस्थित थे।
इंफ्रास्ट्रक्चर के दबाव को सीमित करने के लिए तकनीकी का युक्तिपूर्ण उपयोग करना होगा – सांसद श्री शर्मा ने कहा कि जनसंख्या का दबाव और बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में दबाव बढ़ता है, इस दबाव को सीमा में रखने के लिए आधुनिक तकनीकी का युक्तिपूर्ण रूप से उपयोग अहम है। इस दिशा में ट्रांसपोर्ट प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उन्होंने कहा कि सेमिनार में प्रबुद्धजनों के मंथन से निकले निष्कर्ष का उपयोग शहरी विकास में किया जायेगा। प्रेसिडेंट सीईएआई श्री आरएस शर्मा ने संगठन की संरचना और कार्यों की विधिवत जानकारी प्रदान की। सीईएआई के वाईस प्रेसिडेंट श्री जेवीएल नारायण ने सेमिनार के विभिन्न विषयों की सक्षिप्त जानकारी प्रदान की।

पटवारी बोले-कांग्रेस भी थाने में करेगी सुंदरकांड पाठ

भोपाल में भाजपा नेताओं को अनुमति देने वाले टीआई की पुलिस कमिश्नर से शिकायत ; सर्येंड करने की मांग



भोपाल (नप्र)। भोपाल में अशोकागार्डन थाने के अंदर बने हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के सुंदरकांड पाठ करने पर सियासत तेज हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य नेता शुक्रवार को टीआई हेमंत श्रीवास्तव की शिकायत करने पीएचक्यू पहुंचे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से टीआई को सर्येंड करने की मांग की। पटवारी ने कहा कि दो दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी थाने में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हर धर्म का त्योहार मनाएंगे। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने टीआई को कारण बताओ नोटिस दिया है। टीआई के जवाब मिलने के बाद आगे कार्रवाई होगी।

सर्विस रूल्स और एससी गाइडलाइन का दिया हवाला- पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, मुकेश नायक और पीसी शर्मा शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मिले। कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को अशोका गार्डन थाने में हुए पूरे घटनाक्रम और टीआई हेमंत श्रीवास्तव की भूमिका की शिकायत की। दिग्विजय सिंह ने सरकारी कर्मचारी के सर्विस रूल्स के बारे में बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया।

पटवारी बोले-कमिश्नर ने मांगा दो दिन का वक्त- पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने कहा- जैसे थाने के अंदर भाजपा नेताओं को सुंदरकांड की अनुमति मिली, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सुंदरकांड का पाठ करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का पहला मुद्दा ही संविधान की रक्षा का था। सर्विस बुक का रूल तोड़ना कर्मचारियों ने अपना शौक बना लिया है।

सर्विस बुक की शपथ की अवहेलना हुई- पटवारी ने कहा कि अशोका गार्डन थाने में कल जो हुआ वो मैसेज है कि जो सर्विस बुक की शपथ की अवहेलना हुई है। अब तक टीआई को सस्पेंड कर देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि या तो आप सर्विस बुक का पालन करो या कांग्रेस पार्टी को अपने निजी आयोजनों के लिए अनुमति दो। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं ने पीएचक्यू में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मिलकर टीआई की शिकायत की।

पुलिस कमिश्नर ने कहा-निजी अनुमति नहीं दी जा सकती- पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने कहा- एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है।

नगरीय सुशासन – मानव अधिकार विषय पर आयोजित होगा म.प्र. मानव अधिकार आयोग का 30वां स्थापना दिवस समारोह

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल का 30 वां स्थापना दिवस आगामी 13 सितम्बर, 2024 (शुक्रवार) को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित होगा। मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को बैठक में आयोग के अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने यह जानकारी दी।

आयोग के अध्यक्ष श्री ममतानी ने आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि नगरीय सुशासन-मानव अधिकार विषय पर आधारित स्थापना दिवस समारोह की तैयारियाँ समय पर पूर्ण कर ली जाये। उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाए। श्री ममतानी ने कहा कि नगरीय सुशासन को मानव अधिकार से लिंक किया जाए। उन्होंने जनहित के मुद्दे को शामिल करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा। श्री ममतानी ने बताया कि मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि आवास एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे।

बैठक में आयोग के सदस्य श्री राजीव कुमार टंडन, पुलिस महानिरीक्षक, रजिस्टार लॉ, उप सचिव, पुलिस अधीक्षक, शोध अधिकारी और अनुभाग अधिकारी उपस्थित रहे।

पर्यावरण

डॉ. सौरभ मालवीय

लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

भारत सहित विश्व के अधिकांश देश पर्यावरण संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रीष्मकाल में भयंकर गर्मी पड़ रही है। प्रत्येक वर्ष निरंतर बढ़ता तापमान पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में गर्मी के कारण प्रत्येक वर्ष हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। यह सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। यह पृथ्वी की सहद का दीर्घकालिक ताप है, जो मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न हुआ है। विगत कुछ दशकों में जिस तीव्र गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है वह चर्चा का विषय है। इसके भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कहीं सूखा पड़ रहा है तथा भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। लोग पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के निवासी भी जल संकट से जूझ रहे हैं। कहीं अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दिल्ली के अनेक क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आते रहते हैं। देश की राजधानी को इस स्थिति से पता चलता है कि समस्या कितनी गंभीर है। इससे देश के अन्य क्षेत्रों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है।

मानव अपने स्वार्थ के लिए निरंतर प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है। वनों से वृक्ष काटकर उन्हें समाप्त किया जा रहा है। विकास के नाम पर भी वृक्ष काटे जा रहे हैं। पर्वतों में खनन किया जा रहा है। मानव ने वन समाप्त करके वन्य प्राणियों के लिए आश्रय एवं भोजन का संकट उत्पन्न कर दिया है। कृषि भूमि पर कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। इससे कृषि भूमि कम हो रही है। अत्यधिक रसायनों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। इससे निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक जल स्रोत तालाब, जोहड़ व अन्य जलाशय समाप्त हो रहे हैं। नदियां अत्यधिक दूषित एवं विषैली हो रही हैं। इससे जलीय जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। प्लास्टिक कचरे से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए समस्त जीवों को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के ‘परि’ एवं

‘आवरण’ से मिलकर बना है अर्थात जो चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, हमें उसे संरक्षित करना होगा अर्थात् हमें अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करना होगा तथा इसे जीवन के अनुकूल बनाना होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण पर गंभीरता से कार्य करना होगा। यह सर्वविदित है कि मानव शरीर पंचमहाभूत से निर्मित है, जिनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी सम्मिलित है। प्राणियों के लिए वायु एवं जल अत्यंत आवश्यक है। उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन भी चाहिए, जो भूमि से प्राप्त होता है। वनों से हमें जीवनदायिनी औषधियां प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें वायु, जल, वन एवं मृदा को संरक्षित करना होगा।

जल संरक्षण के लिए प्राकृतिक रूप से बने जलाशयों को संरक्षित करना होगा। नए तालाब बनाने होंगे। जल संग्रहण करना होगा अर्थात् वर्षा के जल को विभिन्न विधियों से संचित करना होगा। तालाब एवं जोहड़ों के अतिरिक्त भूमि के नीचे बनाए गए टैंक के माध्यम से भी वर्षा जल संचयित किया जा सकता है। इसके साथ-साथ जल को व्यर्थ बहने से रोकना होगा। जितनी आवश्यकता हो, उतने ही जल का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नदियों एवं अन्य जलाशयों को प्रदूषित होने से भी बचाना होगा।

मृदा का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए रिक्त पड़ी भूमि पर पौधारोपण किया जा सकता है। इससे एक ओर हरियाली में वृद्धि होगी, तो दूसरी ओर मृदा कटाव रुकेगा तथा भूमि ऊसर होने से भी बचेगी। इसके अतिरिक्त हानिकारक औद्योगिक कचरे को समाप्त करके भी भूमि को दूषित एवं ऊसर होने से बचाया जा सकता है। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैलों का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को कम किया जा सकता है।

वनों का संरक्षण करके भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। वन संरक्षण का उद्देश्य यह कि वनों को कटने से बचाया जाए तथा अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। यदि कहीं विकास कार्यों के कारण वृक्ष काटने अति आवश्यक हों, तो उनसे अधिक संख्या में पौधारोपण किया जाए, जिससे उनकी कमी को

पूर्ण किया जा सके। वन विभिन्न प्राणियों के आश्रय स्थल है। इन्हें सुरक्षित रखकर वन्य जीवों के आश्रय स्थल की भी रक्षा की जा सकती है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए देश में कई अधिनियम हैं। इनमें भारतीय वन अधिनियम-1927, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम-1972, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम- 1974 तथा 1977, वन संरक्षण अधिनियम- 1980, वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम- 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986, जैव-विविधता



संरक्षण अधिनियम- 2002, राष्ट्रीय जलनीति-2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति- 2004 एवं वन अधिकार अधिनियम- 2006 प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।

सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दो अग्रणी पहल की हैं। प्रथम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, जो पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। विगत 13 अक्टूबर, 2023 को अधिसूचित ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक अभिन्न बाजार-आधारित व्यवस्था है जिसे व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कर्पनियों जैसे

विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वेच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका शासन ढांचा एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा समर्थित है तथा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रशासक के रूप में कार्य करता है। यह कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रोग्राम अपने प्रारंभिक चरण में दो प्रमुख गतिविधियों जल संरक्षण और वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रीन क्रेडिट देने के लिए प्रारूप



पद्धति विकसित की गई है और हितधारक परामर्श के लिए इसे अधिसूचित किया जाएगा। ये पद्धतियां प्रत्येक गतिविधि अथवा प्रक्रिया के लिए मानक निर्धारित करती हैं, जिससे सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव और प्रतिस्थापना सुनिश्चित की जा सके। एक उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म परियोजनाओं के पंजीकरण, उसके सत्यापन और ग्रीन क्रेडिट जारी करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा। विशेषज्ञों के साथ भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया जा रहा ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पंजीकरण और उसके बाद ग्रीन क्रेडिट के क्रय एवं विक्रय की सुविधा प्रदान करेगा।

द्वितीय इंकोमार्क योजना है, जिसका उद्देश्य

पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के पीछे का दर्शन व्यक्तिगत विकल्पों और व्यवहार को स्थिरता की ओर ले जाना है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी इंकोमार्क अधिसूचना को फिर से तैयार किया है, ताकि उपभोक्ता उत्पादों के बीच चयन करने में सक्षम हो सकें और इस तरह उन उत्पादों को चुन सकें जो उनके डिजाइन, प्रक्रिया आदि में पर्यावरण के अनुकूल हैं। जो जलवायु परिवर्तन, स्थिरता और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को



प्रोत्साहन देने के लिए देश के सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देती हैं। ये योजनाएं परंपरा एवं संरक्षण में उपस्थित पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की अवधारणा के विचारों को प्रदर्शित करती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं- ‘हमारे लिए पर्यावरण की रक्षा आस्था का विषय है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ियों ने इन संसाधनों की रक्षा की। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी प्रयासों से भारत पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस पहल करने वाला अग्रणी देश बना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने पर्यावरण

संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को दर्शाने वाली एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात ‘जलवायु परिवर्तन विभाग’ वाला देश का प्रथम राज्य बना था। यह एक अनूठा प्रयास था, जबकि तब केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण मंत्रालय ने भी जलवायु परिवर्तन की अवधारणा को एकीकृत नहीं किया था।

लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के ‘भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024’ नामक घोषणा पत्र में पर्यावरण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को विश्व ने स्वीकार किया है। इस मंत्र को साकार करने के लिए हमने पर्यावरण प्रबंधन के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली में विश्व का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पारंपरिक ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक प्रथाओं का उपयोग करके एक स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हों। हमने कई ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की हैं, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। जैसे प्रधानमंत्री सूर्य का घर योजना, रेलवे का विद्युतीकरण, ई-बस, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार एथेनॉल और बांयो फ्यूल का उपयोग इत्यादि। इन सब योजनाओं से हम नेट जीरो के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से अग्रसर हैं तथा इन योजनाओं से हमारे नागरिकों के लिए वातावरण सुनिश्चित होगा।

विगत विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर ‘एक पौधा मां के नाम’ नामक अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने एक्स पर लिखा था- ‘मैंने प्रकृति मां की रक्षा करने और सतत जीवन शैली अपनाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप एक पेड़ लगाया। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप भी हमारे ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान दें।’

इसमें दो मत नहीं है कि सरकारी प्रयास एवं जनभागीदारी से पर्यावरण को संरक्षण किया जा सकता है। हमें अपने बच्चों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

स्वच्छ भारत के नक्शे में क्यों नजर नहीं आती स्लम बस्तियां?

मुद्दा

ईशा कुमारी



देश को स्वच्छ बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों से केंद्र के स्तर पर लगातार प्रयास किये जाते रहे हैं. एक ओर जहां स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है वहीं दूसरी ओर राज्य के साथ साथ शहरी स्तर पर भी स्वच्छता सर्वेक्षण कराये जा रहे हैं. जिसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है. इसमें देश के सबसे साफ शहर को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जाता है. स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग में बिहार को 27 राज्यों में 15वां स्थान मिला है. वहीं इस सर्वेक्षण में बिहार के 142 शहर शामिल हुए थे. इस बार के सर्वेक्षण में राजधानी पटना ने अपनी स्थिति को सुधारा अवश्य है लेकिन अब भी वह टॉप 10 की सूची से बहुत दूर है. एक लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में पटना की आल इंडिया रैंकिंग 77 रही. यह सर्वेक्षण बताता है कि एक राजधानी के तौर पर पटना को स्वच्छता की दिशा में अभी और कई महत्वपूर्ण कदम उठाने बाकी है. दरअसल पटना के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां आज भी साफ़-सफाई बहुत अधिक नजर नहीं आती है. इन्हीं में एक अदालतगंज स्थित स्लम बस्ती भी है. जहां स्वच्छता का विशेष प्रभाव नजर नहीं आता है. पटना सचिवालय से कुछ ही दूरी पर स्थित इस स्लम बस्ती की आबादी लगभग एक हजार के आसपास है. जहां करीब 60 प्रतिशत ओबीसी और 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय निवास करते हैं. तीन मोहल्ले अदालतगंज, ईंख कॉलोनी और झाड़वर कॉलोनी में विभाजित इस स्लम परिया में साफ़ सफाई की बहुत कमी नजर आती है. हालांकि स्वच्छ भारत के तहत कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी यहां आती हैं. जिससे यहां के लोगों का कहना है कि यह गाड़ियां नियमित रूप से नहीं आती हैं, जिसके कारण गंदगी और कूड़े का ढेर जमा हो जाता है. जिससे आसपास की हवा प्रदूषित होती है और इसका प्रभाव यहां रहने वाले बच्चों की सेहत पर देखने को मिलता है. इस संबंध में बस्ती की 18 वर्षीय नंदिनी कहती है कि ‘हमारे बस्ती की स्थिति बहुत दयनीय है. जहां तहां कूड़ा फैला रहता है. जो सड़क और नाली में बहता है. जिससे निकलने वाली दुर्गंध से लोग परेशान रहते हैं. वहीं 70 वर्षीय रामकली देवी कहती हैं कि ‘कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध से सांस लेना मुश्किल हो जाता है. प्रतिदिन कचरा गाड़ी के नहीं आने के कारण अक्सर लोग अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं. जिससे कॉलोनी की हवा प्रदूषित होती रहती है.’ यह कहती हैं कि ‘यदि इन कूड़े को कॉलोनी से बाहर फेंकने के लिए कोई एक स्थान नियमित कर दिया जाए तो समस्या का हल निकल सकता है. लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा ऐसा नहीं करने दिया जाता है. वहीं कूड़े वाली गाड़ी जब नियमित रूप से नहीं आएगी तो लोग अपने घर का कूड़ा इधर उधर ही फेंकेगें.’ वहीं 32 वर्षीय पिकी देवी कहती हैं कि ‘जब कचरा उठाने वाली गाड़ी कॉलोनी में नहीं आती है तो हम अपने घर का कचरा बाहर रख देते हैं. जिसे आबारा कुत्ते खाने की लालच में फाड़ कर इधर उधर बिखरा देते हैं. अक्सर वह कचरे या तो कॉलोनी की रोड पर पड़े होते हैं या उड़ कर नालियों में चले जाते हैं.’ पिकी देवी कहती हैं कि अक्सर कॉलोनी के बच्चे गिप्स और कुड़कुड़े खाकर उसके पैकेट नालियों में फेंक देते हैं. जिससे वह जाम हो जाता है और उसका गंदा पानी सड़क और आसपास के घर तक पहुंच जाता है. जिससे न केवल लोगों को परेशानी होती है बल्कि इससे बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना रहता

है. अब बारिश का मौसम आ गया है. ऐसे में इन कचड़ों की वजह से जाम होती नालियां और भी अधिक उफनने लगेंगी. इसका पानी आसपास के घरों के अंदर तक चला जाता है. यदि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां प्रतिदिन आएंगी तो इस प्रकार की समस्या का काफी हद तक हल संभव है.’ वहीं 12वीं में पढ़ने वाली 17 वर्षीय निकिता कहती है कि ‘अक्सर कॉलोनी की लड़कियां माहवारी के दौरान इस्तेमाल किये पैडस को सही जगह डंप करने की बजाए इधर उधर फेंक देती हैं. जिन पर मखियायां बैठती हैं और वही मखियायां फिर लोगों के खाने पर बैठ कर उन्हें दूषित कर बीमार कर देती हैं. अधिकतर किशोरियां इससे फेलने वाली बिमारियों से अनजान होती हैं.’ वह कहती है कि इसके बारे में कई बार स्कूल में भी बताया जाता है और लड़कियां इसका ख्याल भी रखती हैं, लेकिन घर पर इसके उचित निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण वह इसे खुले में फेंकने पर मजबूर हो जाती हैं. कॉलोनी की बुजुर्ग सुष्मा देवी कहती हैं कि पटना में कई स्थानों पर विकास कार्य चल रहे हैं. इसके तहत पुल और ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है. अदालतगंज के करीब भी आवागमन को सुलभ बनाने के लिए एक पुल का निर्माण किया जा रहा है. इसके लिए इस स्लम बस्ती के पास से गुजरने वाले बड़े नाले को ब्लॉक कर दिया गया है. जिससे उसका सारा गंदा पानी अदालतगंज और झाड़वर कॉलोनी में फैल रहा है. इससे जहां लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर यह बिमारियों का भी कारण बनता जा रहा है. अब जबकि मानसून ने बिहार में दस्तक दे दी है तो बारिश में इसका पानी और भी तेजी से फैलने का खतरा बन जाएगा. इस स्लम बस्ती में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की सैनिका लक्ष्मी देवी और सहायिका मेजर देवी बताती हैं कि इस बस्ती में कोई भी आशा कर्कर की नियुक्ति नहीं है. ऐसे में यदि कोई गंभवर्ती महिला या बच्चे बीमार होते हैं तो वही उन्हें अस्पताल में एडमिट कराने का काम करती हैं. अधिकतर बच्चे गंदगी से फैलने वाली बीमारी के शिकार होते हैं. यदि इस स्लम बस्ती में साफ सफाई का समुचित ध्यान रखा जाए तो बहुत से बच्चों को बीमारी से बचाया जा सकता है. वह कहती हैं कि अक्सर लोग जागरूकता के अभाव में स्वच्छता के महत्व से अनजान रहते हैं. जिसकी वजह से वह घर के कूड़े को इधर उधर फेंक देते हैं. वहीं समाज सेविका फलक कहती है कि ‘इस स्लम परिया के लोगों का कहना सही है कि कई बार दो तीन दिनों तक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी यहां आती ही नहीं है. लेकिन यदि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाए तो इसका समाधान निकाला जा सकता है. इसके लिए बस्ती वालों को सामाजिक स्तर पर योजनाबद्ध रूप से काम करने की जरूरत है. सूखे और गीले कचरे को अलग कर उसके डंप करने की व्यवस्था करने की जरूरत है.’ वह कहती हैं कि हर बात के लिए सरकार और प्रशासन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. यदि कॉलोनी के लोग सामाजिक रूप से इसका हल तलाशें तो प्रतिदिन कचरे का स्थाई निस्तारण संभव हो सकता है. स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में जिन मापदंडों के आधार पर स्वच्छ शहर का चयन किया गया था उसमें कूड़ा इकठ्ठा करना, ट्रांसपोर्ट करना, कूड़े को प्रोसेस और नष्ट करना, सस्टेनेबल सैनिटेशन, इलाके का सौंदर्यीकरण, अतिक्रमण और नाली के पानी का ट्रीटमेंट प्रमुख रूप से शामिल था. इस आधार पर यदि हम अदालतगंज के इस स्लम बस्ती का जायजा लें तो इसमें काफी कमियां नजर आएंगी. हालांकि इस कमी को दूर किया जा सकता है. लेकिन केवल प्रशासन और नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारी डाल कर हम इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं बल्कि इसके लिए सामाजिक स्तर पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है. यह बताने की जरूरत है कि यदि कचड़ा उठाने वाली गाड़ी किसी कारणवश नहीं आती है तो इसका अस्थाई प्रबंधन किस प्रकार किया जाए कि वह इधर उधर न फैले. शायद इस प्रकार के छोटे छोटे कदम ही अदालतगंज जैसे स्लम बस्तियों को स्वच्छ भारत के नक्शे पर प्रमुखता से उभार सकते हैं. (चरखा फीचर)

दृष्टिकोण

बादल सरोज

लेखक लोकजतन के संपादक हैं।



कुछहजार करोड़में बने और अभी अभी प्राणप्रतिष्ठित बताये जाने वाले अयोध्या के मन्दिर की रिसन और उसकी ओर जाने वाली सड़कों का पाताल में समाना रुका भी नहीं था कि पुल गिरने लगे। ऐसे गिरे कि गिरते ही जा रहे हैं और खरबूजे को देखकर खरबूजे रंग बदलते हैं की तर्ज पर गिरते पुल को देख पुल गिरते हैं की नई कहावत गढ़ रहे हैं। रफ्तार कुछऐसी है कि एक के गिरने की धमक रुकती नहीं कि दूसरा टूटकर टपक जाता है। बिहार में अकेले एक दिन में 5 पुल गिरे, 19 दिन में 13 गिरे - इन पिकियों के लिखते लिखते उनकी संख्या 15 हो गयी है। इनकी देखा देखी पड़ोसी राज्य झारखण्ड की अरणा नदी का पुल गिर गया तो दूरस्थ प्रदेश उत्तराखण्ड में एक पुल पूरे का पूरा ही बह गया। मध्यप्रदेश में पिछली बारिश में ही इतने सारे गिर चुके थे बाद में गिरने के लिए लागभग कोई बचा ही नहीं। इतिहास में इस कालखण्ड को पुलों के टूटने, दरकने, गिरने और बहने के कालखण्डके नाम से जाना जाएगा। ये पुल अपने आप नहीं गिर रहे हैं - अनायास नहीं गिर रहे हैं; - इन्हें गिराने के समुचित प्रबंध किये गए थे, खूब जतन के साथ इन पर अमल किया गया था। ईंट-गारे, बजरी, सीमेंट के गिरे हुए पुल थोड़ा शोर, थोड़े स्यापे, एक दूसरे के सर पर हांडी फोड़ने और मिलमिलाकर एक दूसरे को साफ़ बचाने के कर्मकाण्ड के बाद फिर से गिरने के लिए एक बार फिर बना दिए जायेंगे। मगर असली चिंता उन पुलों की है और जिन्हें कारपोरेट की गोद में बेटे हिन्दुत्व के कुनबे ने हमशा के लिए गिरा देने का बीड़ा उठया हुआ है। मौजूदा निजाम ने सत्ता में पहुँचने के बाद पुलों ड़ुहर तरह के पुलों - को तोड़ने और कमजोर करने का काम ही तो किया है। हजार, दो हजार, पाँच हजार साल में बने पुलों को हिलाने, उनकी नींवों को झकझोरने, उनमें पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभ्यताओं के निर्माण की असल कहानी अनगिनत पुलों के बनने और बनाए जाने की कहानी है। जंगल से निकलने के बाद अलग अलग कबीलों, कुटुम्बों, नस्लों, प्रजातियों और संस्कृतियों ने एक दूजे तक पहुँच बनाने के लिए धीरज के साथ ऐसे पुल बनाए जिनसे आना और जाना दोनों सहज बनाया जा सके। संस्कृतियाँ इसी मेल जोड़ से बनी संवरी, सभ्यताओं ने इन्ही पुलों के मजबूत ढाँचों की बुनियाद पर खड़े होकर अपनी ऊँचाईयाँ हासिल कीं और यही तक पहुँचीं। कच्चे अधबने मकानों को घर में और घरों के योग को समाज के रूप में ढाला भी- संजोया भी। ऐसे वैसे कई युग गुजरने के बाद यही समाज राज्यों और देशों के रूप में संगठित और पुनर्गठित हुए। खुद भारत इसकी जीती जागती और अनूठी मिसाल है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्द कविता ‘भारत तीर्थ’ में विस्तार से इसे दर्ज किया। उसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि; ‘हे मोर चित्त पुण्य तीर्थ जागो रे धीरे /एँ भारतेर महामानवेर सागर तीरे / हेथाय दांडाप डु बाहू बाडये / नमि नर देवतारे / हेथा आर्य हेथा अनार्य शक-हुन दल पाठन-मोगल एक देहे होलो लीन / एँ भारतेर महामानवेर सागर तीरे / दांडरे धीरे !’ (कोई नहीं जानता किसके आह्वान पर मनुष्य की

कितनी धारारें प्रबल वेग से आई, किधर से आई और मिल कर भारत के मानवों के महासागर में हो गयी विलीन। यहाँ आर्य हैं अनार्य, हैं द्रविड़ और चीनी, शक, हूण के जत्थे, मुगल और पठान सब एक देह में लीन। पश्चिम के द्वार खुले हैं आज, सब वहाँ से ला रहे हैं उपहार/ इस भारत के महामानव के समुद्र तट पर वे/ दोंगे और लेंगे, मिलायेंगे और मिलेंगे। जायेंगे नहीं लौट कर।)

इसे ही फ़िराक गोरखपुरी साहब ने अपनी तरह से कहा कि;

‘सरजमीने हिन्द पर अक्राम-ए-आलम के फ़िराक काफ़िले बसते गए, हिन्दोस्तां बनता गया।' (अक्रामे आलम = दुनिया भर की कोमों) यहां सिर्फ़ दो का कहा लिखा गया है। किन्तु यही बात भारत में मौजूद 8 भाषा परिवारों की 1652 मातृभाषाओं और 19500 बोलियों में किसी न किसी तरह से दर्ज की



गयी। उस संस्कृत और फारसी में भी जिसे आर्य और बाकी आगंतुक अपने साथ लाये थे, उन द्रविड़ भाषाओं में भी जिन्हें इन सबके आने के सैकड़ों वर्ष पहले से यहाँ रहने वालों ने संजोकर रखा था।

बहरहाल ऐसा, रातोंरात अपने आप नहीं हो गया था। गुरुदेव जिन्हें मनुष्य की कितनी धारारें और फ़िराक जिन्हें दुनिया भर की कोमों बताते हैं वे शक, हूण, कुषाण, यवन, तुर्क, मंगोल, पठान, गुर्जर, आर्य, पारसी, यहूदी और क्रिस्तान और उनसे हजारों साल पूर्व पाँव पाँव यूरोप और एशिया की तय करते अफ़्रीकन, हिन्दुकुश के पर्वतों, हिमालय की श्रृंखलाओं और घाटियों को लांघते, असीम कष्ट सहते इस भूखण्ड पर आये और फिर यहीं के होकर रह गए। रहते बसते आपस में जुड़ने के लिए पुल बनाये, दिया भी लिया भी, मिले भी मिलया भी और इस तरह के अनगिनत पुलों से बना वह हिन्दुस्तान जिसे अब भारत देट इज इंडिया के नाम से जाना जाता है और जिसकी तासीर ‘कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी / सदियों रह है दुश्मन दौर जर्मा हमारा’ के सूत्र में अल्लामा इकबाल ने बयान की है।

कुल जमा यह कि भारत घाटियों का जोड़ है ड़ुधर की उधर की ईंटों के मेलमिलाप का जोड़ है - इन्ही पुलों के मेल और जोड़ से खिली है अनेकता में एकता की शानदार मिसाल विविध संस्कृतियों वाली रंगबिरंगे फूलों की बगिया। इस देश का दुर्भाग्य है कि उसकी बागडोर उनके हाथों में हैं जो इन पुलों को तोड़ने और बगिया को उजाड़ने में लगे हैं।

लिहाजा वास्तविक फ़िक्क की बात ये पुल हैं। पहली बारिश में कागज़ की तरह बह गए पुल तो बन बना जायेंगे - लेकिन हजारों साल की बारिश आंधी और बाढ़में अंडि़ा बने रहे ये पुराने पुल अगर दरक गए तो लम्हों की खता की सजा सदियों को भुगतनी पड़ सकती है। इस कुनबे का निशाना अनेकता में एकता की नींव पर है, सदियों पुराने संग साथ पर है। उनके निशाने पर भाषाएँ हैं; वे एक देश एक भाषा के नाम

पर बाकी सबको पहले दोयम दर्जे पर और आखिर में विलुप्ति की कागार पर पहुंचाना चाते हैं। नीट जैसी केंद्रीकृत प्रतियोगी

परीक्षाओं और अपराध की नई संहिताओं के नामकरण के जरिये ये इसकी शुरुआत कर भी चुके हैं। दूसरी भाषाएँ तो हैं

ही उनके निशाने पर खुद उनकी भाषा है जिसे असंस्कारित. अभद्र और अशिक्ष बनाकर दुर्भाषा बन भी रहे है, बना भी रहे हैं।

विधवाओं और शूद्रों को जीवित ही फूंक देने वाले बर्बर युग से थोड़े बहुत सभ्य समाज तक लाने के लिए राजा राममोहन रायों, ईश्वरचंद्र विद्यासागरों, विवेकानन्दों से होते हुए जातिबा और साक्षित्री फूले, पेरियारों और अम्बेडकरों से लेकर सुधार आन्दोलनो और वामपंथ की तहरीकों ने पुल बनाये थे; कुर्गीतियों और अधविश्वास की थंभर पर करने के लिए बनाये गए इन पुलों को ढ़हकर सामाजिक भूगोल को एक बार फिर मनु और गौतमों के ऊबड़ खाबड़ में तब्दील करने की मुहिम छेड़ दी गयी है। बुद्ध, नानक द्वारा तामीर किये गए पुल तोड़ने की धुन में समाज को आईना दिखाने वाले साहित्य और उसके भी प्रयत्नों से बनी संवरी साझी संस्कृति के मजबूत पुलों की जड़ों में मद्गु ढ़ाला जा रहा है।

सबसे योजनाबद्ध हथौड़ा उस शिक्षा पर चलाया जा रहा है जिसने कंदराओं के युग को वापस कन्दरा में धकेल कर, मस्तिष्कों में जमे अधैरों को झ़ाका रोशनी में बदला था। आर्यभट्टों, वराह मिहिर से भाषा और विक्रम करने की मुहिम छेड़ दी गयी है। बुद्ध, नानक द्वारा तामीर किये गए पुल तोड़ने की धुन में समाज को आईना दिखाने वाले साहित्य और उसके भी प्रयत्नों से बनी संवरी साझी संस्कृति के मजबूत पुलों की जड़ों में मद्गु ढ़ाला जा रहा है। सबसे बड़कर संविधान और कानून के राज के उस पुल को ईंट ईंट करके तोड़ा जा रहा है जिसने भारत को भारत बनाया। पुलों के तोड़ने उन्हें झ़कझोरने की धमकी पुरी श्रृंखला है जिसे गिनाने के लिए यह स्थान पर्याप्त नहीं होगा.; सार की बात यह है कि मनुष्य और उसका समाज कोई स्थिरांक नहीं है - हमेशा गतिशील है। यह गति यदि आगे की ओर नहीं होगी तो पीछे की रपटली ढ़लान की तरफ होगी। मनुष्य के ईसान बरतने की सम्भावनाओं के जितने भी पुल हैं यदि वे तोड़ दिए जायेंगे तो उसका हैवान बनना तय है। उसे बर्बर बनाने की मुहिम भी जारी है।

युद्ध शास्त्र बताता है कि पराजित होकर पीछे की ओर भागने वाली सेनाये जिन पुलों से गुजरती हैं उन्हें ध्वस्त करती जाती हैं। मौजूदा हुक्मरान भी कुछइसी तरहका आचरण कर रहे हैं। ठीक यही वजह है कि नदी नालों पर बने पुलों के गिरने के दोषियों की शिनाख़्त करते हुए, उन्हें सजा दिलाने की मांग उठाते हुए, समाज को जोड़ने वाले पुलों को तोड़ने वालों की पहचान करना और उन्हें उनके इस अपराध के लिए दण्डित करने के लिए भी उठना होगा। अच्छे बात है कि जिन दिनों में ये हमले तेज हुए हैं उन्ही दिनों में इनके खिलाफ़ प्रतिरोध भी बढ़ा है।

